

इन आंकड़ों को प्रस्तुत करने से तात्पर्य है कि खाद्यान्न में यह वृद्धि से अधिक रही है जो कि संतोषजनक स्थिति है और अभी तो भोजन पेट भर मिल रहा है लेकिन प्रश्न यह 2025 में हमें पेट भर भोजन प्राप्त होगा? अगर नहीं तो हम आगे क्या करेंगे?



जनसंख्या एवं खाद्यान्न उत्पादन

भारत की जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार 102.7 करोड़ को छू चुकी है जो 1991-2000 तक 1.9 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि में रही, जबकि खाद्यान्न उत्पादन 2003-04 में 213.5 मिलियन टन तक पहुंचा अथात् 2.1 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर से।

इन आंकड़ों को प्रस्तुत करने से तात्पर्य है कि खाद्यान्न में यह वृद्धि से अधिक रही है जो कि संतोषजनक स्थिति है और अभी तो भोजन पेट भर मिल रहा है लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या 2025 में हमें पेट भर भोजन प्राप्त होगा? अगर नहीं तो हम आगे क्या करेंगे?

हमें अगे भी 21वीं सदी के बाद से खाद्यान्न में लगभग 25-30 प्रतिशत की वृद्धि कामय रखनी होगी अन्यथा पूरे देश हमारा सूखा घोषित हो जायेगा जिससे की लगभग 14 प्रतिशत उत्पादन में गिरावट होगी जो भविष्य के लिए प्रतिटि के उत्तम सक्रिय नहीं है।

भूमि-जल पर्यावरण

खेती में उर्वरकों, कीटनाशकों शाकनाशियों अथात् स्यावनों के अत्यधिक प्रयोग में भूमि की दशा निश्चय ही खराब हो जाती है, जिससे की भूमि के लाभदायक कीट, केन्द्री, जीवाणु इत्यादि नष्ट हो जाते हैं, साथ साथ सूक्ष्म तत्वों में भी भारी कमी हो जाती है। अब: जीवाणु खेतों के प्रयोग से हम रोक सकते हैं फसल चक्र अपना सकते हैं उर्वरकों का संतुलित प्रयोग



कर सकते हैं कई जंगल भी नष्ट किये गये सबन पद्धतियों के प्रयोग के कारण जिससे पर्यावरण संतुलन बिंबित है अथात् इसका देखन कम किया जाए एवं इन्हें संरक्षित किया जाने का प्रयास करना नितान्त आवश्यक है।

लागू/खर्च अनुपात

हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्न

की उपलब्धि बनाये रखने के लिए सभ्य रसायनों का प्रयोग निरंतर बढ़ता ही जा रहा है, जिससे की हमारी भूमि में मृदा में तथा मृदा के गुणों पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। यदि यह प्रक्रिया लंबी अवधि तक चलती रही तो भूमि जल की उपायेता समाप्त हो जायेगी और नई पीढ़ी की जीवन ही असुरक्षित हो जायेगा वर्तमान में हमारे देश

की उपलब्धि बनाये रखने के लिए सभ्य रसायनों का प्रयोग निरंतर बढ़ता ही जा रहा है और कृषि क्षेत्र बराबर कम होता जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में हम टिकाऊ खेती का प्रयोग करना अलंत आवश्यक है तभा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का इसका इस प्रकार से प्रयोग किया जाए कि वर्तमान व भविष्य दोनों में संतुलन हो। इस प्रकार की खेती का प्रयोग करके हम अपने भविष्य की

पीढ़ी को सुरक्षित तो कर रही है बल्कि हमें प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा एवं सुरक्षा करके या उन्हें सुरक्षित बनाये रखने का कर्तव्य भी पूरी तरह निभा रहे हैं। अर्थात् हमें टिकाऊ खेती का प्रयोग किया जाना चाहिए जिसके द्वारा हमें अधिक लाभ एवं भारत सरकार को पूर्ण: उत्पादन से लाभ प्राप्त हो सके।

कृषि क्षेत्र में सम्पन्नता लाने के लिए उत्पादकता टिकाऊपन तथा समाजता की बहुत जरूरत है हमें भारत में भी बदलते पर्यावरण में कृषि निवासी की प्रशिक्षितता देनी अविवायित आवश्यकता है, इसका मुख्य उद्देश्य भविष्य में हम अधिक दृष्टि से कारोग, पर्यावरण की दृष्टि त्रिलोगीन समाजिक दृष्टि से सुरक्षात् प्रौद्योगिकों जो कम लागत पर अधिक से अधिक कृषि उत्पाद दें सकें।

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि टिकाऊ खेती मानव जलि को निरंतर खुशहाली प्रदान का वचन देती है।

मृदा, जल, ऊर्जा, वन-विकास एवं जगती पशुओं की सुरक्षा या इन्हें सुरक्षित रखने से है, टिकाऊ खेती में इनके प्रबंधन पर विशेष प्रकार से ध्यान दिया जाता है, कई प्रकार की उत्पन्न समस्याओं जैसे- सौर ऊर्जा का उत्पादन से वातावरण प्रदूषण की रोकथाम पर्यावरण का संतुलन डगमान इत्यादि समस्याओं पर विशेष रूप से ध्यान देना ही इसमें निम्न विषय है अर्थात् भविष्य में टिकाऊ खेती का प्रयोग से समस्याओं को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है।

टिकाऊ खेती का लाभ:

- परिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाये रखने में टिकाऊ खेती का प्रभाव कार्य है।
- वातावरणीय प्रदूषण कम होता है।
- लगाइ फसलों की उत्पादन लागत कम आती है।
- प्राकृतिक संसाधनों का दोहन उत्पादन प्रकार से करते हैं।
- टिकाऊ खेती में भूमि, जल, ऊर्जा इत्यादि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग हम इस प्रकार से करते हैं कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियां इसका प्रयोग एवं दोहन ध्यान रखकर कर सकें।

धनिया की उन्नत खेती



भूमि

अस्थिरित धनिया के लिये काली मिट्टी जिसकी जलधारा क्षमता एवं भूमि निकास वाली अच्छी भूमि हो और स्थिरित धनिया बोने के लिए दोमट एवं बलुई दोमट मिट्टी स्वीकृत म होती है जिसमें जीवाणु की मात्रा पर्याप्त होती है।

खेत की तैयारी

अस्थिरित खेत में अतिम वर्षा जल की नमी को संरक्षित करते हुए 2-3 जुताई रक्त कर यारपान बुवाई करें तथा स्थिरित खेत में खीरफ फसल को कटाई के बाद 2-3 जुताई करें।

बुवाई का समय

रवी में बुवाई के लिये 15 अक्टूबर से 30 नवम्बर तक उपर्युक्त समय है। दोरी बुवाई करने पर भूमियों रोग की संभवाना बढ़ जाती है।

उन्नत जातियां

साबना, पंत हारितामा, गुजरात धनिया, सिंधु खाता, उदयपुर धनिया-20



ललित गग

वरिष्ठ नागरिक इस योजना का लाभ निजी व राजकीय अस्पतालों में ले सकते हैं। वहीं सरकार की ओर से बताया गया है कि जो सत्र साल से अधिक के नागरिक प्राइवेट बीमा योजना का लाभ ले रहे हैं, वे भी नई योजना का लाभ लेने के अधिकारी होंगे। लेकिन उन्हें इस योजना के लिये आवेदन करना होगा। सरकार ने फिलहाल इस योजना के लिये करीब साढ़े तीन हजार करोड़ का बजट रखा है और आवश्यकता पड़ने पर बजट बढ़ाने की बात कही है।

संपादकीय

हड्डियां का क्या औचित्य

पश्चिम बंगाल में प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले में डॉक्टरों की करीब 33-34 दिनों से जारी हड़ताल अब राज्य के जनजीवन को अराजकता की ओर धकेल रहा है। वास्तव में डॉक्टर और सरकार दोनों पक्षों ने अतिवादी रूप अपनाया हुआ है। बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आंदोलनकारी डॉक्टर के साथ बातचीत करने के लिए करीब 2 घंटे तक इंतजार करती रही, लेकिन डॉक्टर्स बैठक की कार्रवाई का सीधा प्रसारण करने की अपनी मांग पर अड़े रहे। ममता बनर्जी ने उनकी इस मांग को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह मामला समीप कोर्ट में विचाराधीन है। इसलिए बैठक का सीधा प्रसारण



सरकार की विवशतओं को भी समझना चाहिए। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई अपना काम कर रही है। आरजी कर अस्पताल के प्रिसिपल को गिरफ्तार किया जा चुका है। पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए सभी वैधानिक और प्रशासनिक प्रक्रियाएं चल रही हैं। सरकार देर से ही लेकिन आप अब अपना काम कर रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी पीड़िता को न्याय दिलाने के साथ-साथ यह भी आश्वासन दिया है कि डॉक्टरों ने काम पर न लौटकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया है, लेकिन बावजूद इसके सरकार उनके खिलाफ किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी। इसलिए डॉक्टरों को हड्डिताल जारी रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। उनके हड्डिताल से सरकारी अस्पतालों पर इलाज के लिए आश्रित रहने वाली गरीब और बेसहारा जनता के बारे में भी डॉक्टर को विचार करना चाहिए। बेहतर यही होगा कि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए जो भी न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रिया चल रही ही उसे परिणति तक पहुंचाने का इंतजार करे। अमर न्याय नहीं मिलता है तो वह दोबारा आंदोलन शुरू कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने की जो पेशकश की है वह भावनात्मक रूप से आम जनता को प्रभावित करने का प्रयास है। राजनीतिक लोक संकट के समय इस तरह के राजनीतिक दांव खेलते रहे।

चिंतन-मनन

कैंची काटती है, सुई जोड़ती है

कैंची काटती (तोड़ती) है और सुई जोड़ती है। यही कारण है कि तोड़ने वाली कैंची पैर के नीचे पड़ी रहती है और जोड़ने वाली सुई सिर पर स्थान पाती है। इसलिए मनुष्य का यही धर्म है कि इनसान को जोड़े न कि तोड़े। उन्होंने सास-बहू में एका होने का आह्वान भी किया। राष्ट्र संत तरुण सागर महाराज ने कई उदाहरणों के माध्यम से अपनी बातें रखीं। एक पिता अपने छोटे से पुत्र को विश्व का एक नक्शा देता है। फिर उसे टुकड़े-टुकड़े कर पृत्र को जोड़ने के लिए कहता है। पुत्र उस नक्शे को ज्यों का त्यों जोड़ देता है। अपने बेटे की प्रतिभा से आश्रयचकित पिता पूछता है कि बेटे तुमने यह असंभव कार्य कैसे कर लिया। बेटा कहता है कि पिताजी, नक्शा के पीछे इनसान बना हुआ था। मैंने इनसान को जोड़ा तो नक्शा भी ज्यों का त्यों जुड़ गया। मुनिश्री ने कहा कि इनसान को जोड़ने से पूरा विश्व एक हो सकता है। ह मानव 36 का आँकड़ा बहुत बना लिए, अब 63 का आँकड़ा बनाइए। बुजुर्गों के अनुभव का बखान करते हुए मुनिश्री ने कहा कि बुजुर्ग की एक-एक दुर्री पर एक-एक शास्त्र का ज्ञान लिखा होता है। बुजुर्ग की अवहेलना मत करिए। वे जो कह रहे हैं, उसे सुनो। उल्टा जवाब मत दो। जवाब दोगे तो घर का माहौल खराब हो जाएगा। झांगड़ा, क्लेश व द्वेष फैलेगा। बुजुर्गों का सम्मान करना सीखो। आज जो बुजुर्गों के साथ करोगे, वहीं तुम्हारे साथ होगा।

स्वामी, प्रकाशक और मुद्रक डा० सरवर जमाल ने आर० डी० प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स प्रा० लि० प्लाट नं० 16-17 पाटलिपुत्रा इंस्ट्रीयल एरिया, रोड नं० झा० 09 पटना झा० 800013 से छपवाकर कार्यालय 203 बी, लाक रंजीत रेसीडेंसीज, साकेतपुरी, मछली गली, राजा बाजार पटना- 800014 से प्रकाशित किया। सम्पादक: श्रीमती शबाना प्रवीन पी० आर० बी० एकट के तहत खबरों की जिम्मेवारे मैनेजिंग एडिटर: डा० राजीव कुमार, स्थानीय सम्पादक: डा० नूतन कुमारी, उप सम्पादक: तबस्सम नवाज। PRGI NO:- BIHHIN/2023/86924 E-mail- Newsindoqulf730@gmail.com Mob-9472871824/8544031786 समस्त विवादों का निवारण पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे।

बुढ़ापे का स्वास्थ्य सुरक्षा कवच बनाने की सराहनीय पहल

ੴ

द्र सरकार ने अब सत्तर साल से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को ह्यायुप्राप्त भारतह योजना में शामिल करने का निर्णय लिया है, जो सुखद एवं धन्यवाच कदम है। अपने देश के करीब साड़े चार करोड़ के छह करोड़ बुजुर्ग इस योजना के अंतर्गत मुफ्त करा सकेंगे। दरअसल वर्ष 2018 में शुरू हुई योजना में अब तक केवल गरीब परिवार ल हो सकते थे, जिन्हे पांच लाख का कैशलेस या जाता था। अब इस सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना सभी बुजुर्गों को दिया जाएगा। इस योजना से हम दुनिया बना सकेंगे जहाँ हर बुजुर्ग अपने बुढ़ापे आत्मसम्मान, सुरक्षा और स्वस्थता के साथ जी इसके लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं उनकी प्रणालीकारी सरकार को साधुवाद दिया जाना चाहिए। एवं सामाजिक घोर उपेक्षा एवं उदासीनता के द्वापा अपने आप में एक रोग ही बनता गया है। जब स्रोत सिमट जाते हैं और बच्चों से पर्याप्त मदद नहीं तो शरीर में रोग दस्तक देने लगते हैं, फिर महर्गे की चिंता और बढ़ जाती है। संयुक्त परिवारों के और एकल परिवारों के बढ़ते चलन ने इस स्थिति परापर से बाहर कर दिया है। उमीद की जानी चाहिए, न की नयी पहल का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन यह फैसला इस आयुर्वर्ग के बुजुर्गों की सेहत को सुरक्षा कवच का काम करेगा। यह जरूरत इसलिए स की जा रही थी क्योंकि आने वाले बीस वर्ष में बुजुर्ग आबादी तीन गुना होने की संभावना है। अत-विकसित भारत की उन्नत एवं आदर्श संरचनाओं की सम्पादनजनक स्थिति के संभव नहीं है। यदि के वृद्ध कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तथा में बिस्तर पर पड़े कराह रहे हैं, भरण-पोषण एवं लज्जा एवं शर्म का विषय है। वर्तमान युग की डम्बना एवं विसंगति है कि वृद्ध अपने ही घर की पर सहमा-सहमा खड़ा है, वृद्धों की उपेक्षा स्वस्थ स्कृत परिवार परम्परा पर तो काला दाग है ही, यवस्थाओं के लिये भी लज्जाजनक है। हम आदी एकांगी एवं संकीर्ण सोच की तंग गलियों में हैं हैं तभी वृद्धों की तांखों में भविष्य को लेकर भय सुरक्षा और दहशत है, दिल में अन्तहीन दर्द है। इन एवं डरवानी स्थितियों से वृद्धों को मुक्ति दिलाने एवं वास्थ्य विषयक खर्चों एवं चिन्ताओं को दूर करने केन्द्र सरकार ने आयुप्राप्त भारत प्रधानमंत्री जन योजना के अन्तर्गत 70 वर्ष और उससे अधिक

हत्या के अब राज्य में डॉक्टर हस्पितिवार व्यौत करने वैठक की है। ममता बाबा कि यह ग्रामीणों की मार्ग वजह है वर्थन प्राप्त कोर्ट के बाप पर लौट देश की बुजुर्गी। डॉक्टर बूढ़ से यह सर्वोच्च करें। उन्हें वै समझना चाहिए। आरजी वैडित को चल रही रही है। साथ यह कोर्ट के नार उनके ए डॉक्टरों है। उनके हने वाली गार करना ए जो भी न पहुँचाने वैलन शुरू शक्ष की प्रयास है। एवं खेलते

कि तोड़ने वाले सिर पर जोड़े न हो। राष्ट्र संत वातें रखीं। एवं फिर उसे नक्शों को कित पिता बटा कहता नक्शान को के इनकाना आँकड़ा नमुन्भव का पर एक करए। वे तो घर का बुजुर्गों का व्याप्ति साथ

छले छह महीनों के दौ इलेक्ट्रोनिक सामानों की मरही है। इस वर्ष के दौ सामानों के नियात में सालाना आप्रतिशत की वृद्धि हुई। वित वर्ष 2024 तिमाही में पिछले वर्ष की समान अवधि तुलना में इसमें 21.64 प्रतिशत की वृ उत्पादन के क्षेत्र में इस क्षेत्र में अपार सं इस दिशा में मजबूत फोकस राष्ट्रीय फ (जीवीसी) की मदद से इसकी वृद्धि है। भारत में अब ज्यादा से ज्यादा रो उपलब्ध कराने की जरूरत है और इ

पि छले छह महीनों के दौ इलेक्ट्रोनिक सामानों की मरही है। इस वर्ष के दौ सामानों के नियात में सालाना आप्रतिशत की वृद्धि हुई। वित वर्ष 2024 तिमाही में पिछले वर्ष की समान अवधि तुलना में इसमें 21.64 प्रतिशत की वृ उत्पादन के क्षेत्र में इस क्षेत्र में अपार सं इस दिशा में मजबूत फोकस राष्ट्रीय फ (जीवीसी) की मदद से इसकी वृद्धि है। भारत में अब ज्यादा से ज्यादा रो उपलब्ध कराने की जरूरत है और इ

संजय गोस्वामी

नरेन्द्र भारती

दे श में बढ़ती रैगिंग की घ रुकती यह एक वक्ष प्रश्न ब हिमाचल का बहुचर्चित अ कांड के बाद भी विश्वविद्यालयों व का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। न्यायलय ने रैगिंग पर पर्ण प्रतिबंध किया है मगर देश में रैगिंग के बढ़ कानून मजाक बनता जा रहा है। त हिमाचल के वाकनाघाट में एक निज में प्रथम वर्ष के एक छात्र से रैगिंग व में आया है रैगिंग के आरोपी तीन छ कर लिया है व हॉस्टल व यूनिवर्सिटी है। इससे पहले आईआईटी मंडी में सामने आई थी' आईआईटी प्रबंधन छात्रों को छ: महीने विश्वविद्यालय दिया था तथा 72छात्रों पर 15 से 25 का जुमार्ना लगाया गया था' यह अगस्त 2023 को घटित हुआ था' अ घटित यह बहुत ही संगीन मामला है प्रशासन को कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। मामले बढ़ते ही जा रहे हैं' रैगिंग के छात्र आत्महत्या तक कर रहे हैं त विलासपुर में भी एक मामला हो चुक छात्रा ने आत्महत्या की कोशिश की थी' यूजीसी के आकड़ों के मुताबिक रैगिंग के 219 मामले सामने आये थे के 511मामले हुए थे' 2019 में उत्त में सैरफई मैटिकल विश्वविद्यालय में



आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय लाभ देने का फैसला लिया है, वह सराहनीय एवं प्रासारिक निर्णय है। इसके फैसले की जरूरत इसलिए थी क्योंकि सामाजिक सुरक्षा के मामले में भारत बहुत पीछे है। गण्डीय परिवर्तन स्वास्थ्य सर्वे 2019-21 की रिपोर्ट से पता चलता है कि देश में ऐसे परिवारों की संख्या केवल 41 प्रतिशत है, जिनके कम से कम एक सदस्य का स्वास्थ्य बीमा हो। बिहार, महाराष्ट्र जैसे बड़ी आबादी वाले राज्यों में तो यह राष्ट्रीय औसत के करीब आधे के बराबर है। स्वास्थ्य बीमा को लेकर यह उदासीन रवैया हमारी उसके आदत की वजह से है, जिसमें ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि जब बीमारी आएगी तो देखा जाएगा। बहुत से लोग जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा को एक ही चीज समझते हैं। लेकिन, जब बीमारी सिर पर आती है, तो पूरे घर के बजट को तहस-नहस एवं असंतुलित कर देती है। सरकार का मौजूदा कदम कई परिवारों को ऐसे आर्थिक दुष्कर्त में फंसने से बचा सकता है। भारत में इलाज दिनों-दिन महंगा होता जा रहा है। जब आय के स्रोत सिमट जाते हैं और बच्चों से पर्याप्त मदद नहीं मिलती तो शरीर में रोग दस्तक देने लगते हैं, फिर महोगी इलाज की चिता और बढ़ा जाती है। अकसर भारत में कर्मचारी व आम लोग सोचते हैं कि वे जीवन भर आयकर चुकाते हैं, लेकिन बुढ़ापे में

सरकार की ओर से सामाजिक सुरक्षा ना के बराबर होती है। लेकिन अब मोदी सरकार ने लोकतंत्र के सामाजिक कल्याणकारी स्वरूप को तरजीह दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं उनकी सरकार अनेक स्वस्थ एवं आदर्श समाज-निर्माण की योजनाओं को आकार देने में जुटी है, उसने वृद्धों को लेकर भी चिन्तन करते हुए वृद्ध-कल्याण योजनाओं को लागू किया है। इन योजनाओं को लागू करने की जरूरत इसलिये सामने आयी है कि वृद्धों को आत्म-गौरव के रूप में स्वीकार करने की अपेक्षा, बंधन माना जाने लगा है। वृद्धों को लेकर जो गंभीर समस्याएं आज पैदा हुई हैं, वह अचानक ही नहीं हुई, बल्कि उपभोक्तावादी संस्कृति तथा महानगरीय अध्युनातन बोध के तहत बदलते परिवारिक-सामाजिक मूल्यों, नई पीढ़ी की सोच में परिवर्तन आने, महंगाई के बढ़ने और व्यक्ति के अपने बच्चों और पतni तक समित हो जाने की प्रवृत्ति के कारण बड़े-बूढ़ों के लिए अनेक समस्याएं आ खड़ी हुई हैं। अब जब स्वास्थ्य बीमा का दायरा बढ़ाया गया है तो यह उम्मीद की जानी चाहिए कि खर्च को लेकर परिजनों का डर कम होगा। इस योजना का पूरा खाका सामने आना बाकी है। लेकिन यह सुनिश्चित तो करना ही होगा कि बीमा सुरक्षा कवच होने के बावजूद बुजुर्ग मुफ्त उपचार से वर्चित न रह जाएं। खास तौर से सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का

इलेक्ट्रॉनिक सामानों की मांग में तेजी

क्षेत्र महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इस लिहाज से इस क्षेत्र में 2018 से 2022 के बीच रोजगार में सबसे ज्यादा बढ़ोतारी देखी गई है। उम्मीद है कि समीक्षा में भी इस ओर ध्यान दिया गया होगा। हालांकि, दुनिया के 4.3 ट्रिलियन डॉलर के वैश्विक क्वांटम कार्डिन बाजार में भारत की हिस्सेदारी करीब 2 फीसदी है। इस मुद्दे के केंद्र में चीन का खास बाजार है और इन दोनों सम्झौतों का निशाना यह है कि इसके शेयर लगातार 30 के दशक में गिर रहे हैं। द्विनियांग और मालाबाबर जैसे उभरते बाजारों में भी नैतिक रूप से इस क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत की है और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में उनका प्रभाव चौथे स्थान पर पहुंच गया है। इस संदर्भ में निधि आयोग की नई रिपोर्ट हाइलेक्ट्रॉनिक्स: पारविंग द इनफ्लुएंसर्स इन जीईसीइल में उल्लेख किया गया है कि 2017 से 2022 के बीच इलेक्ट्रिक प्रौद्योगिकियों का उत्पादन बढ़ोगा और इसमें 13 तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई है। यह निकाय समग्र अवसरों की ओर इशारा करता है, लेकिन आगे के विकास और एकीकरण की चुनौतियों को लेकर विंताएं भी हैं। वर्तमान में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन का उपयोग बाजार में मोबाइल फोन, हेडफोन, रेफ्रिजरेटर और ऐसे अन्य उपकरणों के प्रचार के उद्देश्य से किया जा

हा है। विनिर्माण क्षेत्र इन उपकरणों के आय पर्भर है और डिजाइन के सीमित आकार के लिए दृढ़ती मांग के कारण उपकरणों की उत्पादन भावित होती है इसके अलावा करें और टैक्सों के दृढ़ि हो रही है, जिससे स्थानीय स्तर पर उत्पादिक महंगा हो रहा है। अधिक ऊंचाई के उत्पन्नों के लिए उत्पन्नों से जुम गीतों पर अधिक ध्यान देना रहा है, जिसका सोधा असर सिनेमा में दर्शन दृढ़ हो रहा है। कैल सहित, सामग्री, आवरण और विनिर्माण की लागत पर अधिक व्यय के कारण, 14-18 प्रति वर्ष वास्तविक लागत अक्षमताओं का सामना करना। कोयले की कम खपत और कमजोर वित्ती उत्पादन के बावजूद, भारत इसका लाभ उठाने वाला निश्चिह्न रहा है। उन कारकों का समाधान इन उत्पादन और विनिर्माण को नकारात्मक रूप से भावित कर रहे हैं, जो इन नए लोगों को खुला है हैं। प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों से भारत का बहिष्कार दृढ़ी बाधा है। इन संगठनों का हिस्सा बनने से विनिर्माणों, सरल नियमों और व्यावसायिक अवसरों के दृढ़ि के कारण उत्पादन लागत कम हो सकता है। अरकार के प्रयासों के बावजूद, भारत व्यापार विनिर्माण के लिए अभियान लड़ना चाहता है।

अपने प्रतिद्विद्यार्थियों को पकड़ने के लिए निरंतर ट्रैक पर है। कमाई बढ़ाने के साथ-साथ भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में कड़ा रुख अपनाना होगा और इसमें फोन और अन्य उत्पकरण शामिल होंगे। वर्तमान में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की हिस्सेदारी फोन में 43 प्रतिशत है। स्थानीय स्तर पर सामुदायिक सेवा स्थापित की जा सकती है और उत्पाद तैयार करके जीवन में जान डाली जा सकती है। प्रतिस्पर्धियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ सुविधाएं भी बनाई जा सकती हैं। वर्ष 2024-25 तक राज्य में लोगों को रोजगार देने की भारत सरकार की योजना एक उत्पुक्त कदम है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की समीक्षा के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उत्पकरणों के उत्पादन में तेजी आएगी। यदि इन सभी मुद्दों को एक साथ हल नहीं किया गया तो भारत उन लोगों को लुभाने का अवसर खो देगा जो भारत में चीन के विनिर्माण क्षेत्र पर अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। चीन अपनी नीतियों और कम लागत वाली नियामकीय और राजनीतिक पहलों से उनका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि कार्बावाई की आवश्यकता पर संदेह पैदा करने की जरूरत है।

देश में बढ़ती रैगिंग की घटनाएं क्यों नहीं रुकती?



घटित हुआ था' जहां सीनियर छात्रों ने 150 छात्रों के सिर मुँडवा दिए थे'यह एमबीबीएस के प्रथम वर्ष के छात्र थे' ताकि अपराधियों को सजा मिल सके रैगिंग के मामलों में वृद्धि खतरनाक साबित हो रही है। वर्ष 2018 में ऐसा ही एक मामला मध्यप्रदेश के भोपाल में घटित हुआ था जहां रैगिंग से तंग आकर बीफार्मा की एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी ,छात्रा के सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने चार लड़कियों व एक अध्यापिका को गिरफतार कर लिया था। रैगिंग का यह कोई मामला पहीं हे इस से पहले कई जघन्य वारदातें हो चुकी हैं। इनी वारदातें होने के बाद भी इन घटनाओं पर रोक नहीं लग रही है। रैगिंग छात्रों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। रैगिंग की इन वारदातों से छात्र खौफजदा होते जा रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो छात्रों के भविष्य पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं क्योंकि इन वारदातों से अभिभावक भी अपने बच्चों को असुरक्षित समझ रहे हैं। रैगिंग का साधरण सा अर्थ एक दूसरे का परिचय जानना होता था मगर अब इसका स्वरूप बदलता जा रहा है। रैगिंग अब यातना बन गई है छात्रों को मानसिक रूप से प्रताडित किया जाता है , मारपीट की जाती है। आज तक पता नहीं कितने छात्र-छात्राएं रैगिंग के कारण असमय मौत के मुह में जा चुके हैं।उत्तरप्रदेश के इटावा में घटित इस घटना ने एक नई बहस को जन्म दिया था' देश के शिक्षण संस्थानों में प्रतिबन्ध के बाद भी यह मामले थमने का नाम नहीं ले

हे है। बीते हादसों से न तो प्रशासन ने सबक सीख ली और न ही छात्रों ने सीख ली। यदि कडे कदम उठाए जाएं तो आज यह हादसा न होता। यह एक यक्ष प्रशन बनता जा रहा है रैगिंग की यह बीमारी विश्वविद्यालयों कालेजों के बाद अब स्कूलों में भी अपने पांच प्रसार खुकी है यदि इस पर समय रहतें रोक न लगाई तो अनेक वाले समय में घातक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। दें श में समय समय पर ऐसे दुखद हादसे होते रहते हैं मगर यह रुकनें के बजाए निर्बाध रूप से बढ़तें ही जा रहे हैं सप्तमाचार पत्रों की खबरों के अनुसार मई में मुम्बई के टाइम में रैगिंग से तंग आकर एक छात्र ने ट्रेन के अगे टकटककर आत्महत्या कर ली दिल्ली के स्कूल आफलानिंग एंड अकाईटेक्सर का एक होनहार छात्र रैगिंग के बलतंते अपाहिज हो गया अरोप है कि प्रथम वर्ष के छात्र नवीन कुन्जर को उसके सीनियर ने ऐसी यातना दी कि वह चलने फिरने के काबिल नहीं रहा अन्धप्रदेश में एक कालेज में सीनियर छात्राओं ने जननियर छात्राओं की रैगिंग ली उनकी यातना से उस छात्र न अपनी आवाज खो दी थी एक अन्य घटना में छात्रों को क्लास में लड़की कहा जाता था छात्रों की इस इरकत से तंग आकर उस छात्र ने खुद को आग लगा दी थी। मुम्बई में एक कालेज में सीनियर छात्राओं ने एक जननियर छात्रा को मिर्ची खिलाई और उठक बैठक करवाई कोलकाता में एक कालेज में सीनियर जननियर को डग्स लेने के लिए मजबूर करते हैं और पैटाइ

करते हैं उत्तर प्रदेश में सरकार ने रैगिंग के खिलाफ अधियान छेड़ा है तथा रैगिंग करने वाले छात्रों को पांच साल तक दखिला न देने को कड़ा फैसला लिया है साल 2010 में एक साल में 164 केसों में 19 की मौत हो गई थी। देश में 2023 में भी यह मामले थमते नहीं आ रहे हैं। एक समय था कि कालेजों में रैगिंग का नाम तक नहीं था मगर पिछले कुछ सालों से रैगिंग के आकड़ों में अप्रत्याशित बढ़ोतारी होती जा रही है। कालेज के कुछ बिंगडैल किस्से के छात्र -छात्राएं कालेज का माहौल बिगाड़ने में मशगुल रहते हैं, ऐसे मुठभी भर लोग छात्रों को अनावश्यक रूप से तंग कर रहे हैं ऐसे उदर्दं लोगों को कानून के मुताबिक सजा देनी चाहिए। आज यह रैगिंग भयानक होती जा रही है। बीते सालों में हिमाचल के सुन्दरनगर के पौलिटैक्निक कालेज में भी रैगिंग की वारदात प्रकाश में आई थी जिसमें सिरपौर का एक छात्र रैगिंग का शिकार हुआ था हालांकि कालेज प्रशासन ने उन सीनियर लड़कों को कालेज से निकाल दिया है पर कालेज से निकालना इसका समाधान नहीं है। केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयण को इन मामलों पर संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि यदि समय रहते कारगर कदम नहीं उठाए तो हालात बेकाबू हो जाएंगे छात्र -छात्राएं रैगिंग के डर से प्रवेश नहीं लेंगे कालेजों में अराजकता पैदा करने वाले तत्वों पर कार्रवाई करनी चाहिए इनके कारण कई प्रतिभाएं खत्म हो रही हैं। ऐसे लोगों को सजा दी जाए तथा जुमारी लगाया जाए। ऐसी भी रैगिंग की छात्र पदाई तक छोड़ देते हैं आज तक हजारों छात्र इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं फिर भी यह प्रवृत्ति रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। जनमानस को एकजुट होकर इसका खात्मा करना होगा ताकि छात्र-छात्राएं निर्भिक होकर अपनी पदाई कर सके। रैगिंग के बढ़ते जाल को काटना होगा ताकि भविष्य में इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और शिक्षण संस्थानों में माहौल खराब न हो सके इस बुराई के विरुद्ध एक आनंदोलन करना होगा और प्रतिभावान छात्रों को बचाना होगा रैगिंग का समूल नाश करना चाहिए ताकि यह नासूर न बन पाए। सरकारों को इन मामलों पर संज्ञान लेना होगा तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए। यह देश हित में है

